बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में बस्तियों का विस्तार

द हिंदू

पेपर-I एवं III (शहरीकरण, आपदा प्रबंधन)

भारत के शहरी क्षेत्रों में लगातार बाढ़ आ रही है, जिससे जीवन और आजीविका नष्ट हो रही है। फिर भी विश्व बैंक के नेतृत्व में और 4 अक्टूबर को नेचर में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार कई शहरों में बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है क्योंकि वे बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में विस्तार कर रहे हैं। अखबार के मुताबिक, 1985 के बाद से बाढ़ प्रभावित इलाकों में मानव बस्तियां दोगुनी से भी ज्यादा हो गई हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ये निष्कर्ष भारत में अस्थिर शहरीकरण के जोखिम को उजागर करते हैं। अध्ययन में यह भी पाया गया कि भारत जैसे मध्यम आय वाले देशों में निम्न और उच्च आय वाले देशों की तुलना में बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में अधिक शहरी बस्तियाँ हैं।

भारत को कैसे खतरा है?

भारत उन 20 देशों में शामिल नहीं है जिनकी बस्तियाँ बाढ़ के खतरों से सबसे अधिक प्रभावित हैं, लेकिन यह चीन और अमेरिका के बाद वैश्विक बस्तियों में तीसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता था, बल्कि चीन और वियतनाम के बाद तीसरा - नई बस्तियों का विस्तार करने वाले देशों में भी है। जो बाढ़ प्रवण क्षेत्र में विस्तार कर रहें है। (सभी 1985 से 2015 तक) बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स (IIHS) के एक शोधकर्ता गौतम भान ने कहा कि इसका मतलब है कि भारत बाढ़ से संबंधित समस्याओं के महत्वपूर्ण खतरे में है जो आने वाले वर्षों में और भी खराब हो सकती है। यदि देश सावधान नहीं होता है।

डब्ल्यूआरआई इंडिया के भू-विश्लेषक, राज भगत पलानीचामी ने ईएम-डीएटी नामक डेटाबेस के अध्ययन से कहा कि - "मारे शहरी क्षेत्रों और पेरी शहरी क्षेत्रों में बाढ़-प्रवण क्षेत्रों का अध्ययन करने के लिए आवश्यक ग्रैन्युलैरिटी" नहीं हो सकता है। बाढ़ से संबंधित खतरों के केंद्र में "जहां हम अपने शहरों का निर्माण या विस्तार करते हैं," श्री पलानीचामी ने 2022 में लिखा था। उन्होंने अनुमान लगाया था कि उस वर्ष बेंगलुरु शहर को बाढ़ से 225 करोड़ का नुकसान हुआ था। 1901-2022 में, शहर की जनसंख्या लगभग 1.6 लाख से बढ़कर एक करोड़ से अधिक हो गई। इन लोगों को समायोजित करने के लिए, शहर का विस्तार हुआ - लेकिन नए इलाकों ने स्थानीय "स्थलाकृति" को नजरअंदाज कर दिया, श्री पलानीचामी ने कहा।

सबसे अधिक प्रभावित कौन हैं?

श्री पलानीचामी और डॉ. भान दोनों इस बात से सहमत हैं कि अनौपचारिक संरचनाओं में रहने वाले लोगों के लिए जोखिम अनुपात गैर-अनौपचारिक संरचनाओं से अधिक है। जैसा कि डॉ. भान ने कहा, "पर्यावरणीय जोखिम का भूगोल अनौपचारिक कम आय वाले आवास का भूगोल भी है।" उन्होंने कहा, शहरों में अनौपचारिक आवास "ऐसी जमीन पर है जो खाली है और कम वांछनीय है, ताकि उन्हें तुरंत हटा न दिया जाए।" इसलिए वे अक्सर "निचले, बाढ़-प्रवण क्षेत्रों" में रहते हैं।

डॉ. भान के अनुसार, शहरीकरण का बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में विस्तार होने का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि "हमारे पास यह कहने के लिए शासन प्रक्रियाएं नहीं हैं, इस प्रकार का विकास पर्यावरणीय रूप से अस्थिर है'।" जब पर्यावरणीय नियम लागू होते हैं नए निर्माणों के लिए, इन्हें अक्सर केवल बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर लागू किया जाता है, न कि इलाकों के मध्यम और छोटे पैमाने के संशोधनों के लिए। यह इस धारणा का खंडन करता है कि कुछ इलाके अधिक बाढ़-प्रवण हैं और बाढ़ का खतरा स्थानीय स्तर के मुद्दे हैं।

डॉ. भान ने कहा कि लोग आमतौर पर मौजूदा सरकारी नियमों का उल्लंघन करते हैं। उन्होंने वन भूमि पर इको-टूरिज्म रिसॉर्ट्स में वृद्धि और नदियों के बाढ़ के मैदानों पर सरकारी भवनों और यहां तक कि धार्मिक संरचनाओं सहित बड़ी संरचनाओं के निर्माण के उदाहरणों का हवाला दिया।

क्या किया जाना चाहिए?

जैसे-जैसे शहरों का विस्तार जारी है, श्री पलानीचामी और डॉ. भान ने आगाह किया कि हम अब बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में विस्तार करने से बच नहीं सकते। श्री पलानीचामी ने कहा, "बाजार की ताकतें बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में विस्तार को बढ़ावा देती हैं।" "लेकिन यह पहचानना कि ये क्षेत्र क्या हैं और हम वास्तव में इनमें विस्तार कर रहे हैं, स्थायी शहरी नियोजन की दिशा में पहला कदम है जो जोखिमों को संबोधित करता है।" डॉ. भान ने कहा, अनुकूलन के कुछ रूप आवश्यक हैं, और उन्हें कम आय वाले निवासियों और अभिजात वर्ग के लिए बनाई गई अनधिकृत संरचनाओं के बीच अंतर करने की आवश्यकता है।

श्री पलानीचामी ने कहा, "प्रत्येक शहर को बाढ़ प्रवण क्षेत्रों का उचित वैज्ञानिक मानचित्रण करने की आवश्यकता है।" डॉ. भान ने कहा कि शहरी सरकारों को ऐसे क्षेत्रों में आवास को अधिक बाढ़ प्रतिरोधी बनाने और कम आय वाले आवास की रक्षा करने की आवश्यकता है। उन्होंने नदी किनारे की बस्तियों का उदाहरण दिया, जिनमें स्टिल्ट हाउस का उपयोग किया जाता है, जैसे कि ब्रह्मपुत्र के किनारे मिशिंग और मिया समुदायों द्वारा उपयोग किया जाता है।

संभावित प्रश्न (Expected Question)

प्रश्न : बाढ़ क्षेत्रों में मानव बस्तियों से संबंधित विश्व बैंक की रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. विश्व भर में बाढ़ क्षेत्रों में मानव बस्तियों में वर्ष 1985 के बाद से 122% की वृद्धि देखी गई है।
2. सबसे सुरक्षित क्षेत्रों की मानव बस्तियों में 80% की वृद्धि देखी गई।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

Que. Consider the following statements with reference to the World Bank report related to human settlements in flood zones:

1. Human settlements in flood zones around the world have seen a 122% increase since 1985.
2. Human settlements in the safest areas saw an 80% increase.

Which of the statements given above is/are correct?

(a) Only 1

(b) Only 2

(c) Both 1 and 2

(d) Neither 1 nor 2

उत्तर : c

संभावित प्रश्न व प्रारूप (Expected Question & Format)

प्रश्न : "पर्यावरणीय जोखिम का भूगोल अनौपचारिक कम आय वाले आवास का भूगोल भी है।" इस कथन के संदर्भ में कम आय और पर्यावरणीय जोखिम के संबंधों का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर का दृष्टिकोण:

- ❖ उत्तर के पहले भाग में प्रश्न में दिए कथन की व्याख्या करें।
- ❖ दूसरे भाग में कम आय और पर्यावरण जोखिम के संबंधों का उदाहरण सहित विश्लेषण कीजिए।
- ❖ अंत में आगे की राह दिखाते हुए निष्कर्ष दें।

नोट : अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्त्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।